09072015-ls-ngp-04.qxd 07/09/2015 11:33 AM Page 1

और... एक शेर

शराफ़तों की यहां कोई अहमियत ही नहीं
किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है
-वसीम बरेलवी

लोकमत समाचार
नागपुर, गुरुवार, 9 जुलाई 2015

लोकमत समाचार

तमसो मा ज्योतिर्गमय

सिंह की शूरता और पुष्प की कोमलता के साथ जीवन भर काम करते रहो. ■ विवेकानंद

संपादकीय

दुनिया की अगुवाई करने का मौका

दुनिया के विकासशील देशों की हालत बेहतर बनाने में अब तक चीन का योगदान अधिक रहा है, लेकिन अब भारत की बारी है और अगले 15 साल में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने में भारत विकासशील देशों की अगुवाई करेगा. यह बात नीति आयोग के सदस्य एवं जाने-माने अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय ने सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) पर संयुक्त राष्ट्र की सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कही है. जाहिर है कि यह विश्व में भारत की बढ़ती हैसियत को दर्शाता है. दुनिया के लिए अब किसी भी मामले में भारत की अनदेखी करना संभव नहीं रह गया है. ऐसा नहीं है कि भारत ने यह हैसियत रातोंरात हासिल कर ली है. इसमें पिछली सरकारों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें बड़ी भूमिका है. उन्होंने विश्व परिदृश्य में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महती भूमिका निभाई है. लेकिन यह समय यहीं पर संतुष्ट होकर रुक जाने का नहीं है. विश्वशक्ति बनने के लिए हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना होगा. बेशक आज हम चीन की बराबरी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर चीन के अनुभवों से सीख लेंगे तो हमें और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. चीन की सफलता सिर्फ कुछ वर्षों की ही मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि उसने 1980 के दशक से ही इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था. चीनी लोगों ने अत्यंत कठोर परिश्रम के बल पर ही आज अपने देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है. हालांकि यह भी सच है कि यह परिश्रम चीनी सरकार द्वारा लोगों पर लादे गए कठोर अनुशासन का नतीजा रहा है. चीन अपने यहां लोकतंत्र के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों का कठोरता से दमन करता रहा है. वहां के श्रम कानून श्रमिक विरोधी रहे हैं. भारत और चीन के बीच यही फर्क है. हमारे यहां का लोकतंत्र विश्व के लिए आदर की वस्तु है. इसलिए चीनियों जैसा कठोर परिश्रम अगर हम स्वेच्छा से करें तो चीन से बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि बाहर से लादे गए अनुशासन की अपेक्षा स्वानुशासन हमेशा श्रेष्ठ होता है. दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं के होने का लाभ भी इस समय हमारे देश के पास है. युवा अगर ठान लें तो क्या कुछ नहीं कर सकते? बहरहाल, भारत और चीन के प्रयासों से दुनिया काफी हद तक गरीबी के चंगुल से बाहर आई है. घोर गरीबी में रहने वालों की संख्या 1.9 अरब से घटकर 83.6 करोड़ पर आ गई है. भुखमरी का अनुपात भी 23.3 फीसदी से घटकर 12.9 फीसदी रह गया है. चीन की अर्थव्यवस्था चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है, उससे आगे बढ़ने की अब गुंजाइश नहीं है. एक संतान नीति के कारण वहां की जनसंख्या में भी युवाओं के बजाय बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो चुकी है. इसलिए अब भारत को मानकर चलना चाहिए कि दुनिया को बेहतरी की दिशा में ले जाने की अगुवाई अब उसे ही करनी है. कठोर परिश्रम को अगर हम अपना मूलमंत्र बना लें तो यह काम आसानी से कर सकते हैं. ■■

दोजख

लघुकथा

भगीरथ

आंखों में शीशे की किरचें चुभ रही थीं. बीच बाजार में खून से लथपथ लाश पड़ी थी. बिल्कुल अकेली. जिस भीड़ में वह था, अब वह गलियों, गलियारों में भागती हुई चाय घरों और सिनेमा-घरों में घुस गई थी. सिर्फ वह साक्षी था, जिसने पूरी घटना को घटते हुए देखा था. उसने आंखें बंद कर लीं, नहीं देखा जाता. उसने ईश्वर से दुआ मांगी- प्रभु ये आंखें वापस ले लो और उस दिन वह अंधा हो गया.

दृश्य बेमानी हो गए थे, लेकिन अब दूसरी इंद्रियां ज्यादा संवेदनशील हो गई थीं. अब वह लाठियों के सहारे चलता तो आवाजों से ही सब कुछ पता लगा लेता. अब उसे आवाजें परेशान करने लगीं. मारो, काटो, विधर्मी है. इतने में ट्रक से कुचलता हुआ साइकिल सवार कि.. कि.. बिचारा. उसने फिर ईश्वर से दुआ मांगी और वह बहरा हो गया.

इस तरह वह अंधा, बहरा और गूंगा हो गया. यहां तक कि अंत में उसने ईश्वर से दुआ की कि उसके प्राण ही ले ले. ज्यों ही वह यमराज के दरबार में पहुंचा, उसे दोजख की आग में झोंकने की आज्ञा दे दी गई. यह कैसा न्याय है. न मैंने बुरा देखा, न बुरा सुना, न बुरा कहा. फिर यह सजा. प्रभु, तुम तो दयानिधान हो! 'मैंने न केवल तुम्हें जीवन दिया बल्कि उसकी सब उपलब्धियों से परिपूर्ण किया. उसके उपरांत भी तुम लगातार जीवन से भागते रहे, दब्बू और कायर की तरह मेरी रचनात्मक शक्ति का उपहास किया तुमने. इसकी यही सजा है.' और उसे पकड़कर दोजख की आग में झोंक दिया गया.■■

दुनिया दीवानी, घर में परेशानी

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

अश्वमेध घोड़ा भेजे बिना भारत के तिरंगे को दुनिया के विभिन्न शक्तिसंपन्न अथवा कमजोर देशों के राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संचालकों की ओर से सलामी मिल रही है. इस स्थिति पर भारतीयों का गौरव करना स्वाभाविक है. सत्ताधारियों का यह दावा हास्यास्पद है कि यह मात्र एक वर्ष के चमत्कारों से हुई उपलब्धि है. वास्तव में यह पिछले 25 वर्षों के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक तथा सामाजिक प्रयासों का प्रतिफल है.

मोदी और उनके संघ-भाजपाई बंधु-बांधव भले ही जवाहरलाल नेहरू के नाम और काम को इतिहास से मिटाने की हरसंभव कोशिश करना चाहते हों, लेकिन आज भी सत्तर प्रतिशत गरीब गांवों की आबादी वाले विशाल भारत को गुटनिरपेक्ष नीतियां अपनाकर अपने हितों की रक्षा करनी होगी. ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश एक सीमा तक ही भारत का साथ दे सकते हैं. हां, सामाजिक दृष्टि से ईरान, मिस्त्र, ओमान, कुवैत के साथ अच्छे रिश्ते कायम रखना जरूरी है. पिछले वर्षों के दौरान अमेरिका के सारे प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ रिश्ते कमजोर नहीं होने दिए. इसे भारतीय राजनयिक सफलता ही कहा जाएगा कि पाकिस्तान अब आतंकवादी और भारत विरोधी गतिविधियों के कारण अकेला सा दिखने लगा है. यदि चीन भारत के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाकर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से पंजाब तक भारी पूंजी निवेश करता है, तो क्या पाकिस्तान को भारत में विध्वंस के लिए कोई सहायता करना उचित समझेगा? संबंधों की सबसे बड़ी कड़ी है- व्यापार और पूंजी. अमेरिका, यूरोप का बाजार निरंतर कमजोर तथा सीमित हो गया है.

दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं. लेकिन अपने आंगन में बज रहे अनियंत्रित नगाड़े मोदी के लिए तकलीफदेह होते जा रहे हैं.

इसलिए दुनिया के अधिकांश देशों को भारत के महानगरों, शहरों और गांवों तक में धंधे के साथ चांदी चमकती दिख रही है. इसलिए दिग्-दिगंत से 'मोदी की जयकार' सुनी जा सकती है.

दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं. लेकिन अपने आंगन में बज रहे अनियंत्रित नगाड़े मोदी के लिए तकलीफदेह होते जा रहे हैं. सत्ता के एक वर्ष की सफलताओं के बैंड-बाजों की आवाज कुछ घंटों में शांत हो गई और गड़बड़ियों-घोटालों के हंगामे ने भाजपा और सरकार की साख पर धुआं सा फैला दिया है. इसकी असली वजह 'लव-हेट रिलेशन' का रोल है. एक ही पार्टी में रहते हुए भी नरेंद्र मोदी ने सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं से दूरियां बढ़ाकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया. एक समय था, जबकि अयोध्या रथ यात्रा में वह आडवाणी के सारथी थे, मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा में भी वह झंडा उठाकर अग्रिम पंक्ति में थे. संगठन सचिव रहते हुए सुषमा स्वराज के मार्गदर्शन में हरियाणा के गांवों में भाजपा के गीत गाते थे. गुजरात को अधिकाधिक आर्थिक पैकेज दिलवाने के लिए यशवंत सिन्हा की चौखट पर भावभीना प्रणाम करते थे. लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ऐसी सीढ़ियों को ही तोड़ना शुरू कर दिया. सुषमा स्वराज द्वारा ललित मोदी के लिए औपचारिक पत्र के मुद्दे को उनके नजदीकी खेमे ने खूब हवा दी.

इसी तरह वसुंधरा राजे तो पहले दिन से ही उन्हें आंखों में खटक रही थीं. लोकसभा में राजस्थान से सभी पच्चीस सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की विजय के बावजूद वसुंधरा की सलाह पर केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं रखा गया. ललित मोदी विवाद उछलने से मोदी मंडली को यह राहत मिली कि अब वसुंधरा सिर उठाकर नहीं टकरा सकेंगी और उचित समय पर हटवाना आसान होगा. चुनाव से पहले आडवाणी ने म.प्र. में शिवराज की सफलता को एक अर्थ में गुजरात से थोड़ा बेहतर कह दिया था. अप्रत्यक्ष संदेश यह था कि निरंतर विधानसभा चुनाव जितवाने वाले तथा प्रदेश में कांग्रेस को निपटाने वाले शिवराज भी किसी वक्त केंद्र के सिंहासन के हकदार हो सकते हैं. मोदी इस तारीफ को कड़वे घूंट की तरह याद रखे हुए हैं. इसलिए व्यापमं घोटाले में शिवराज सिंह की बदनामी का लाभ कांग्रेस से अधिक मोदी खेमा लेना चाहता है.

इसमें कोई शक नहीं कि फिलहाल भाजपा और मोदी का विकल्प राजनीतिक मैदान में नहीं है. लेकिन नेहरू, इंदिरा-राजीव के बाद कौन, की बात की जाती थी. नरसिंह राव के सत्ताकाल में मैंने भी 'राव के बाद कौन' शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी. तब कांग्रेस में शरद पवार, अर्जुन सिंह, प्रणब मुखर्जी जैसे दिग्गज नेताओं के नाम थे. वहीं मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रबल दावेदार लिखा था. थोड़ी देर से ही सही वह प्रधानमंत्री बने. इसलिए यह धारणा पालना ठीक नहीं होता कि एक चुनाव में भारी समर्थन पाने वाली पार्टी और उसके प्रधानमंत्री का विकल्प चार-पांच वर्षों बाद नहीं दिख सकता. राजनीति का पुराना मंत्र यह था कि - 'अश्वमेध घोड़ा छोड़ने के साथ अपने राजकाज को राम राज्य बनाओ.' ■■

डिजिटल इंडिया के सपने में महंगे इंटरनेट की बाधा

शशांक द्विवेदी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर शोर से देश भर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लांच कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी महंगे इंटरनेट से बहुत परेशानी में है. ये हालात तब हैं जब 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है. पिछले दिनों 1.1 लाख करोड़ रुपए की 2जी-3जी स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार का खजाना तो भर गया लेकिन इसकी कीमत अब आदमी को अपने जेब से चुकानी पड़ रही है. हाल में ही देश की सभी बड़ी दूरसंचार कंपनियों ने इंटरनेट पैक की दरें 40 से 100 फीसदी तक बढ़ा दी हैं. हालात ये हो गए हैं कि सभी प्रमुख कंपनियों ने पिछले सिर्फ एक साल में ही कई बार इंटरनेट डाटा पैक की दरें बढ़ाई हैं जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद उद्योग संगठनों ने इस बात के संकेत दिए थे कि डाटा इस्तेमाल की दरों में बढ़ोत्तरी होगी, क्योंकि ऑपरेटरों को सरकार को करीब 1,09,874 करोड़ रुपए का भुगतान करना है. लेकिन सवाल यह है कि ये भुगतान क्या अब देश का आम आदमी खासकर युवा वर्ग अपनी जेब से करेगा?

एक तरफ सरकार देश में डिजिटल इंडिया का सपना देख रही है वहीं दूसरी तरफ देश की लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियां पिछले एक साल में उपभोक्ताओं के लिए 2जी और 3जी सेवाओं के लिए अपने इंटरनेट पैक की दरें लगातार बढ़ा रही हैं जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लगातार बढ़ने से ये कीमतें कम होनी चाहिए. सरकार डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इंटरनेट की पहुंच गांव-गांव तक करना चाहती है लेकिन बढ़ती हुई कीमतें सभी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी आईटीयू की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट 60 से ज्यादा देशों से महंगा है. आईटीयू के अनुसार किफायती ब्रॉडबैंड देने वाले देशों की सूची में भारत 93वें स्थान पर है, जबकि मोबाइल इंटरनेट पर 67वें स्थान पर है.

अगर एशियाई देशों से ही तुलना करें तो पता चलता है कि भारत में इंटरनेट मॉरिशस, माल्टा और पड़ोसी देश श्रीलंका से भी महंगा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए देश में इंटरनेट दरों का कम होना जरूरी है. इसके लिए केंद्र सरकार को तत्काल कदम उठाने होंगे.

दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को एक ताकत के रूप में देखा जाता है लेकिन भारत में ही चीजें उतनी तेज गति से आगे नहीं बढ़ रहीं जितनी कि बढ़नी चाहिए. एक तरफ देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने की दरें बहुत ज्यादा महंगी हैं वहीं दूसरी तरफ औसत इंटरनेट स्पीड बहुत कम है, मतलब टेलीकॉम कंपनियों द्वारा जितनी बताई जाती है उससे काफी कम उपभोक्ता को मिलती है स्पीड. हमारा

एक तरफ देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने की दरें बहुत ज्यादा महंगी हैं वहीं दूसरी तरफ औसत इंटरनेट स्पीड बहुत कम है.

ब्रॉडबैंड तंत्र काफी अकुशल है और फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आईएसपी) ढांचागत विकास पर उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना कि मुनाफा बटोरने पर दे रहे हैं. दूरसंचार के ढांचे में कई कमियां मौजूद हैं.

हाई स्पीड इंटरनेट और बेहतर सेवा के लिए 3जी जैसी तकनीक देश के हर हिस्से में अभी भी मौजूद नहीं है. इंटरनेट स्पीड और तकनीक के मामले में भारत दूसरे देशों की तुलना में अभी भी बहुत पीछे है. बिजली की उपलब्धता, सस्ती कीमतों पर कम्प्यूटरों तथा डिजिटल युक्तियों की मौजूदगी, शिक्षा, इंटरनेट के इस्तेमाल संबंधी जागरूकता, आम आदमी के लिए आम आदमी की भाषाओं में सेवाएं मुहैया कराने जैसे मोर्चों पर भी सरकारी और गैरसरकारी पहल की तुरंत जरूरत है. जबकि दूसरी पीढ़ी की क्रांति में हम इंटरनेट तथा वेब के जरिए गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दूसरी अन्य चीजों में बदलाव ला सकते हैं. आम आदमी की इस बुनियादी जरूरत पर सरकार को तत्काल संजीदगी दिखानी होगी. ■■

शिवराज की फजीहत

नजरिया उर्दू प्रेस का
■ राजश्री यादव

मध्यप्रदेश के बहुचर्चित और सनसनीखेज व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले पर उर्दू अखबारों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि अगर इस घोटाले की स्वतंत्र जांच की जाए तो हैरतअंगेज बातें सामने आएंगी और कई बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी.

'सहाफत डेली' मुंबई ने लिखा है, मध्यप्रदेश में एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पार्टी वाले राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्यप्रणाली और उनकी ईमानदारी का बहुत गुणगान करते रहते हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में 'व्यापमं' से संबंधित इतना बड़ा घोटाला सामने आया है कि उसके सामने सभी तरह के घोटाले छोटे पड़ जाएंगे. इस घोटाले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे जुड़े 50 लोगों की अब तक संदिग्ध मौत हो चुकी है. इनमें सर्वाधिक चर्चित एमपी के राज्यपाल रामनरेश यादव के पुत्र शैलेष यादव की मौत है. इस फर्जीवाड़े में 1980 सॉल्वरों, दलालों और फर्जी परीक्षार्थियों के साथ-साथ कई बड़े और नामचीन लोग शामिल हैं. राज्यपाल रामनरेश यादव पर भी इस घोटाले में मामला दर्ज है. अगर कांग्रेस की हुकूमत वाले किसी राज्य में इस कदर मौतें होतीं तो भाजपा ने अब तक आसमान सिर पर उठा लिया होता.

ऐसा न हो गत कुछ सालों से जारी सूरते हाल यही रहे और मध्यप्रदेश के नौजवान यूं ही संदिग्ध मौत की आगोश में समाते रहे.

हैदराबाद से प्रकाशित **'मुंसिफ डेली'** ने लिखा है, इस घोटाले की जांच के दौरान अब तक 50 लोगों की संदिग्ध मौत का होना यह साबित करता है कि इससे कितने हाईप्रोफाइल लोग जुड़े हैं. तहकीकात के नाम पर एजेंसियां ऐसा क्या कर रही हैं कि इससे जुड़े लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं या फिर जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि कभी हादसा तो कभी बीमारी की आड़ में उन्हें रास्ते से हटा दिया जा रहा है. और ये ऐसे वक्त हो रहा है जब जांच हाईकोर्ट के हुक्म पर एसआईटी की निगरानी में की जा रही है. निगरानी नहीं होती तो शायद मौतों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच जाती. एसटीएफ इस मामले में आरोपियों से उनकी हैसियत, उनके रसूख के अनुसार सलूक कर रहा है. राज्य सरकार के रहनुमा और ओहदेदार इस मामले में शक के दायरे में हैं और एसटीएफ पर उन्हीं का कंट्रोल है.

'इन्कलाब डेली' दिल्ली ने लिखा है, पूर्व में जितने घोटाले हुए उनमें शायद ही कोई घोटाला ऐसा रहा जो 'टू इन वन' या 'थ्री इन वन' के बजाय 'मेनी इन वन' यानी कई घपलों का एक घोटाला रहा है. व्यापमं घोटाला देर में बहस का मुद्दा बना, लेकिन इसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी. इसे घोटालों का सरताज होने का सम्मान भी हासिल रहेगा, जब तक इससे बड़ा कोई घोटाला इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ देता.■■

और अंत में...
दुनिया में बरकतों का
सिला देता है रोजा
और आखिरत भी अपनी
बना देता है रोजा
इंसानियत का दर्द,
गरीबों की भूख-प्यास
एहसास ऐसे कितने जगा
देता है रोजा (साभार 'उर्दू टाइम्स')

नजर के पार

पिता के बदले माता का नाम क्यों नहीं?

वेदप्रताप वैदिक
वरिष्ठ पत्रकार

भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक क्रांतिकारी निर्णय दिया है. उसने एक अविवाहित माता की इस अपील को स्वीकार कर लिया है कि उसका बच्चा अपने अभिभावक की जगह अपने पिता के बदले अपनी माता का नाम लिखे. अब ऐसे बच्चों को अपने पिता का नाम लिखना या बताना जरूरी नहीं होगा. अदालत का यह निर्णय पढ़ते ही मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्यों नहीं हम सब भारतीय हर जगह अपनी माता का नाम लिखें? पिता का नाम, जिन्हें लिखना है, जरूर लिखें लेकिन किसी भी सरकारी और गैर-सरकारी दस्तावेज पर माता का नाम लिखना अनिवार्य क्यों नहीं होना चाहिए? किसी भी संतान के लिए माता और पिता, दोनों का होना जरूरी है लेकिन माता का सत्य तो तथ्य होता है और पिता का सत्य तो एक अनुमान भर होता है. हम तथ्य के मुकाबले अनुमान को ज्यादा महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा समाज पिता प्रधान है. माता तो स्त्री है. वह तो आदमी की जायदाद है. उसके कोई अधिकार नहीं हैं, सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य हैं. यदि कोई संतान समाज में जानी जाए तो बस वह पिता के नाम से ही जानी जाए. यह विषैली धारणा पश्चिमी और पूर्वी जगत, सभी दूर व्याप्त है.

लेकिन हम जरा पलटकर देखें. भारत में शूर-वीरों को उनके माताओं के नाम से ही जाना जाता था. कुंती के पुत्रों को कौंतेय कहा जाता था और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को सौमित्र. जाबाला के पुत्र सत्यकाम को जाबाल के नाम से जाना जाता था. हम सीता-राम और राधाकृष्ण क्यों बोलते हैं? सीता को राम के पहले और राधा को कृष्ण के पहले स्थान क्यों देते हैं? भारत के लोग अपनी जन्मभूमि को 'फादरलैंड' नहीं कहते हैं. उसे वे मातृभूमि कहते हैं. वेदों में भी पृथ्वी को माता कहा गया है. 'माता भूमिः, पुत्रोऽहं पृथिव्याः'. जब बच्चों के गुरुओं की गणना होती है तो उसमें पिता और आचार्य के पहले माता का नाम आता है. 'मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेदः'. ऐसा क्या हुआ कि पश्चिमी समाज की तरह हमने भी माता को पीछे धकेल दिया? यदि भारत का हर नगारिक अपने अभिभावक की जगह माता का नाम लिखने लगे तो देश में बहुत बुनियादी सामाजिक क्रांति शुरू हो जाएगी.

इस संबंध में मैंने अपने लघु-भ्राता तुल्य डॉ. सूरत सिंह से बात की है. वे प्रसिद्ध वकील हैं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने कानून की पढ़ाई की है. हम प्रयत्न करेंगे कि उच्चतम न्यायालय में शीघ्र ही एक याचिका दायर करें और पिता के बदले माता का नाम लिखना अनिवार्य करवा दें. ■■

यदि भारत का हर नगारिक अपने अभिभावक की जगह माता का नाम लिखने लगे तो देश में बहुत बुनियादी सामाजिक क्रांति शुरू हो जाएगी.

तोल बोल

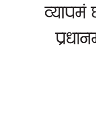

व्यापमं घोटाले को लेकर काफी चर्चाएं की जा रही हैं और मामला संवेदनशील बनता जा रहा है. लिहाजा इस मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए.
■ **सुमित्रा महाजन**, लोकसभा अध्यक्ष

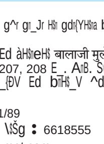

व्यापमं घोटाले में अगर 30, 40, 50 मौतों पर भी प्रधानमंत्री नहीं बोलते तो मुझे हैरानी है कि वह किस बात पर बोलेंगे.
■ **अभिषेक मनु सिंघवी**, कांग्रेस नेता

gñWnH$ gnXH$: nd. Od hab b XS
M`a_Z, E{S Q>{a`b ~moS : {dO` XS
E{S Q>a-BZ-Mr\$: a OÐ XS
gnXH : {dH$mg {_l★
★ nr. Aa. ~r. H$ZZ H$ AZgma gnU gnXH$` X{`Ed H$ {bE {Oå_Xma.

© लोकमत समाचार _ àHmeH g^r g _Jr H$ gdmߪYH$a b H$_V ... बालाजी मुळे ... 192, 207, 208 E_. AmB. S. gr. ...
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaÜd{Z : 0712-2423527 (7 b mBÝg) \$¡Šg : 6618555
Email : gnmXH$s` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkmnZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaU : circ.ngp@lokmat.com

इतिहास पर नजर 9 जुलाई

आज ही के दिन सन 1925 में वसंतकुमार शिवशंकर पादुकोण का जन्म हुआ था. पादुकोण, जो आगे चल कर हिंदी फिल्मों में गुरुदत्त के नाम से जाने गए, उन्हें हिंदी फिल्म जगत के सबसे कमाल के कलाकारों में से एक माना जाता है. प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद तथा साहब बीबी और गुलाम जैसी उनकी फिल्मों को आज तक की बेहतरीन हिंदी फिल्मों की सूची में रखा जाता है. टाइम पत्रिका ने प्यासा और कागज के फूल को आज तक की दुनिया की सौ सबसे अच्छी फिल्मों में जगह दी थी. गुरुदत्त ने एक अभिनेता, निर्देशक और निर्माता तीनों ही रूपों में एक से एक हिट फिल्में दीं. सन 1964 में 10 अक्तूबर को उनकी मृत्यु हो गई. ■■

- ■1686-जर्मनी, स्वीडन और स्पेन के बीच फ्रांस विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर.
- ■1815-अमेरिका में प्राकृतिक गैस के पहले कुएं की खोज.
- ■1816-अर्जेंटीना ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की.
- ■1875-बंबई स्टाक एक्सचेंज की स्थापना की गई.
- ■1917-ब्रिटिश युद्धपोत 'वैनगार्ड' में विस्फोट होने से 804 लोगों की मौत.
- ■1918-अमेरिका के नैशविले क्षेत्र में ट्रेन दुर्घटना में 101 लोगों की मौत, 171 घायल.
- ■1951-देश की पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) की शुरुआत.

पाठकों के पत्र

भूमिहीनों को भूमि दी जाए

हमारा देश यद्यपि अमीर माना जाता है, लेकिन यहां पर गरीब लोग निवासरत हैं. चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां पर लगभग 70% लोग कृषि कार्य करते हैं तथा इसी कार्य से अपने परिवार का पालन-पोषण किया करते हैं. इस देश में आज भी बिहार, राजस्थान, उ.प्र. जैसे राज्यों में कई सामंती भूपतियों, साहूकारों के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है जो उनके रिश्तेदार, नौकर, चाकरों के नाम से लिखी हुई है जहां पर सिलिंग एक्ट का पालन नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा कई लोग भूमिहीन हैं जो कृषि कार्य दूसरों के यहां करते हैं. यद्यपि उन्हें कृषि कार्य का तजुर्बा अवश्य है बेहतर ढंग से कृषि कार्य करते हैं, लेकिन भूमिहीन हैं. साहूकारों भूपतियों के पास सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं, लेकिन उन्हें कृषि कार्य करना नहीं आता फिर भी वे भूपति उसके मालिक बने हुए हैं. भूमि उसकी होनी चाहिए जो उस जमीन को जोतता है उस पर कृषि कार्य करता है. अतः भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान करना चाहिए.
■बी.सी. उके, सिवनी

अफवाह का असर

सूफी कथा

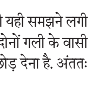

किसी समय एक शहर था, जिसमें दो समानांतर गलियां थीं. एक दरवेश किसी दिन एक गली से दूसरी गली में जा पहुंचा और लोगों ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू हैं. 'दूसरी गली में कोई मर गया है,' एक आदमी ने चीखकर कहा. और तुरंत ही पास के बच्चों ने उसकी बात को सिर पर उठा लिया. वास्तव में हुआ यह था कि दरवेश प्याज छील रहा था. थोड़ी ही देर में बच्चों की आवाज पहली गली में पहुंच गई और दोनों गलियों के सयाने इतने दुखी और भयभीत हुए कि उन्हें चीख-पुकार का कारण जानने की हिम्मत भी नहीं रही.

एक समझदार आदमी ने समझाने की कोशिश भी की, कि कारण का पता लगाना चाहिए. लेकिन तब तक लोग इतनी घबराहट और विभ्रम से भर गए थे कि उन्हें इसका होश भी नहीं रहा कि वे क्या कह रहे हैं. इतने में कुछ लोग बोल उठे : 'हम इतना जानते हैं कि दूसरी गली मारक प्लेग के चंगुल में है.'

यह अफवाह भी जंगली आग की तरह फैल गई. अब हरेक गली यही समझने लगी कि दूसरी गली पर कयामत उतरी है. जब कुछ व्यवस्था लौटी तब दोनों गली के वासी अलग-अलग यही तय कर पाए कि आत्मरक्षा के लिए उन्हें शहर छोड़ देना है. अंततः पूरा शहर खाली कर वहां के सभी लोग अन्यत्र जा बसे.

सदियों बाद अब भी वह शहर उजाड़ है और उससे जरा दूर हटकर दो गांव हैं, जहां की परंपराएं कहती हैं कि उनके पुरखे किसी अज्ञात अनिष्ट से बचने के लिए कभी किसी अभिशप्त नगर को छोड़ कर यहां आए थे. ■■